at Rs. 114 lakhs in 1968-69 rising to Rs. 200 lakhs in 1970-71.

Reorganisation of Beedi Industry in Kerala

1039. SHRI GADILINGANA GOWD:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Kerala have submitted a scheme to reorganise the State's beedi industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED): (a) Yes, Sir. A scheme for the rehabilitation of the displaced beedi workers of the Ganesh, Bharath and Durbar Beedi Factories in Cannanore District has been received from the Government of Kerala.

(b) The scheme relates to the organisation of 20 primary and one central cooperative society to rehabilitate 10,325 beedi workers who have been thrown out of employment consequent on the enforcement of the Beedi and Cigar Act and to provide them with financial assistance by way of grants and loans. The total assistance contemplated for a period of five years is estimated at Rs. 7.07 lakhs as grants and Rs. 108.05 lakhs as loans. The State Government has also suggested that the Reserve Bank should accept the scheme for refinancing and that the State Cooperative Bank should extend financial accommodation to the Central Society on the guarantee of the Government.

(c) The scheme is under examination.

Broad Gauge Railway Line from Pratapnagar to Chhota Nagpur and Rajpipla to Anklesvar Stations

1040. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has proposals of converting Pratapnagar (Baroda) Chhota Nagpur and Rajpipla-Anklesvar into Broad Gauge on the Western Railways;

(b) whether the survey in respect of the aforesaid proposals has been completed; and

(c) if so, the expenditure involved in each of the said proposals?

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) to (c). The Western Railway is at present carrying out a review in'o the working of narrow gauge lines on that system. This review includes Pratapnagar-Chhota Udaipur (and not Chhota Nagpur) and Ankleshwar-Rajpipla narrow gauge sections. The question of conversion of these sections to broad gauge will be considered after the results of this review are known and examined by the Railway Board.

Loan to Public Sector Steel Plant

1041. SHRI BHAGABAN DAS:
SHRI GANESH GHOSH:
SHRI MOHAMMED ISMAIL:
SHRI A.K. GOPALAN:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the total amount of loan given to the public sector steel plants;

(b) whether Government are considering proposals to reduce the loan;

(c) whether one of the proposals for bringing down the loan portion is by additional investment; and

(d) if so, the manner in which the additional capital is likely to be invested?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K.C. PANT): (a) As on 31st March, 1968,

the amount of loans advanced by Government to Hindustan Steel Limited stood at Rs. 5315 million including a short-term loan of Rs. 110 million.

(b) to (d). It had been pointed out in the Pamphlet entitled "Performance of Hindustan Steel Limited" (placed on the Table of the House on 5th April, 1968) that the Steel Plants suffered from certain basic handicaps affecting their working. Some measures designed to remove or minimise these handicaps are presently under examination.

केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर

1042. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5976 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर तथा लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा लघु उद्योगों को किस एजेंसी के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) निगम स्थापित करने का औचित्य क्या है ; और

(ग) उसके कृत्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) लघु उद्योग सेवा संस्थायें लघु उद्योग एककों को वित्तीय सहायता नहीं देतीं। इन्दौर में कोई केन्द्रीय लघु उद्योग निगम नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के एकक

1043. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर के सभी एकक घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य निदेशकों ने इसके कई एकक अवैध रूप से बेच दिये हैं और हजारों श्रमिकों की छंटनी कर दी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जबकि, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन की, कूपर एलन तथा नार्थ-वेस्ट टेनरी शाखायें, कई वर्ष से हानि उठा रही हैं, 1967 में, ऊनी शाखाओं ने भी विशेष क्षति उठाई है।

(ख) तथा (ग). कम्पनी से प्राप्त सूचना के अनुसार, कम्पनी ने अवैध रूप से, अपने किसी एकक को नहीं बेचा है, एवं हजारों श्रमिकों की छंटनी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यदि माननीय सदस्य के विचार, दो चीनी कम्पनियों के हिस्सों तथा इसकी कुछ सहायक कम्पनियों के कुछ बंगलों की बिक्री के बारे में हैं, तो इस विषय पर, उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त, जाँच-प्राधिकारियों द्वारा, विचार किया जायेगा। चीनी कम्पनियों के हिस्सों की बिक्री के बारे में, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष, एक व्यवहार-वाद भी अनिर्णीत है। यदि यह निर्देश, कूपर एलन नार्थ-वेस्ट टेनरी शाखाओं के लिये है, तो उसकी स्थिति यह है कि 14 फरवरी, 1969 को की गई असामान्य साधारण बैठक में, ब्रिटिश इन्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के हिस्सेधारियों ने कथित शाखाओं को सर्वसम्मति से कुछ शर्तों पर, सरकार को हस्तांतरण का अनुमोदन करते हुए एक संकल्प पारित कर दिया है।